भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या** 2762

उत्तर देने की तारीख 10 जुलाई, 2019 (बुधवार)

19 आषाढ़, 1941 (शक)

**प्रश्न**

**उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए परियोजनाएं**

2762. श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवसंरचना के विकास संबंधी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी निधि का आवंटन किया गया है; और

(ख) राज्य की अवसंरचना के विकास से संबंधित स्वीकृति हेतु कौन-सी परियोजनाएं लंबित हैं?

**उत्तर**

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक अवसंरचना परियोजना आरंभ की गई हैं जिनमें सड़क और रेल संपर्क, हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण और विकास, अंतर्देशीय जलमार्ग, दूरसंचार और विद्युत क्षेत्र का विकास की परियोजनाएं शामिल हैं । पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) के तहत संपर्क और सड़क अवसंरचना में सुधार लाने के लिए 6418 किमी लंबी सड़क को मंजूरी दी गई है जिसमें से लगभग 57.518 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से लगभग 5273 किमी सड़क के निष्पादन को मंजूरी दी गई है । मंजूर की गई 5273 किमी सड़क में से 3029 किमी सड़क (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार) को 30,315 करोड़ रूपए के कुल व्यय से पूरा किया जा चुका है। रेल क्षेत्र में जीरीबाम-इंफाल, दिमापुर (धनसिरी)- जुब्जा (कोहिमा), अगरतला-सबरूम, तेतेलिया-बर्नीहाट, बर्नीहाट-शिलांग, भैराबी-सैरांग, मुरोकोंगसेलेक-पासीघाट, अगरतला (भारत)-अखौरा (बंग्लादेश) आदि जैसी परियोजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल संपर्क के विकास हेतु आरंभ किया गया है । पिछले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में नई लाइनों, गेज परिवर्तन और डबलिंग की परियोजनाओं के लिए निम्नानुसार निधियां आबंटित और व्यय की गई हैं:-

*(करोड़ रूपए में)*

| क्र.सं०. | वित्तीय वर्ष | आबंटित निधि | व्यय की गई निधि |
|---|---|---|---|
| 1. | 2014-15 | 5147.52 | 2664.01 |
| 2. | 2015-16 | 5551.95 | 3385.71 |
| 3. | 2016-17 | 6006.89 | 5147.57 |
| 4. | 2017-18 | 4006.84 | 5398.12 |
| 5. | 2018-19 | 4970.97 | 5989.96 |
| **कुल** | | **25684.17** | **22585.37** |

वायु संपर्क के संबंध में गुवाहाटी, इंफाल, अगरतला, दीमापुर, तेजु आदि स्थित हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए परियोजनाएं आरंभ की गई हैं । होलोंगी (ईटानगर) में 645.63 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान की गई है । पैक्योंग में 553.50 करोड़ रूपये की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है और अब यह प्रचालन में है ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 19 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है । राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) नं-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और एनडब्ल्यू-16 (बराक नदी) की परियोजनाओं और 18 नए एनडब्ल्यू के लिए अध्ययन पर पिछले तीन वर्षों में 270.50 करोड़ रूपए का व्यय किया गया है ।

दूर संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत नेट परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि चरणबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों में ब्रॉड बैंड संपर्क प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में 644.55 करोड़ रूपए की लागत से सभी 11,956 ग्राम पंचायतों (चरण-। में 5860 और चरण-॥ में 6096) को जोड़ा जा सके । पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 5336.18 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से विस्तृत दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी) कार्यान्वित की जा रही है ताकि 8621 पहचाने गए और शामिल नहीं किए गए गांवों के लिए 6673 मोबाईल टावर, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए 321 मोबाईल टावर स्थापित किए जा सके और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसारण नेटवर्क को दृढ़ता प्रदान की जा सके ।

विद्युत क्षेत्र में 4754.42 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से अरूणाचल प्रदेश और सिक्किम में संचारण और वितरण तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत स्कीम (सीएसएसटीएंडडीएस) के तहत संचारण और वितरण तंत्र को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाएं और मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और असम राज्यों के लिए 5111.33 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विद्युत तंत्र सुधार परियोजना (एनईआरपीएसआईपी) आरंभ की गई है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने एनएलसीपीआर-राज्य, उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएसडीएस), उत्तर पूर्वी विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईडीएस) जैसी अपनी स्कीमों और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्कीमों के माध्यम से अवसंरचना में अंतरालों को पाटने के लिए परियोजनाएं आरंभ की हैं ।

(ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रकार का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है ।

*****